DELHI POLICE 2025
CONSTABLE
HCM
AWO/TPO
DRIVER
यकीन बैच
POLITY
मूल अधिकार
FUNDAMENTAL RIGHTS
LIVE
05-02-2025 12:10 PM

कल- नागरिकता (Citizenship)

1 March-1947 से पहले पाक. चला गया
भारतीय नागरिकता ×

- **अनुच्छेद 7** – भारत से पाकिस्तन जाने वाले व्यक्ति

  Article 7 - Persons going from India to Pakistan

- **अनुच्छेद 8** – भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार

  भारतीय मूल व्यक्ति

  Article 8 - Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India

- **अनुच्छेद 9** – यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय स्वतः समाप्त हो जाती है।

  Article 9 - If a person voluntarily accepts the citizenship of a foreigner, then his Indian automatically ends.

- अनुच्छेद 10– किसी व्यक्ति नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। ↳ नागरिकता का बना रहना।

Article 10- Citizenship of a person can be taken by parliamentary law.

- अनुच्छेद 11– संसद को नागरिकता से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार है।

Article 11- Parliament has the right to make laws related to citizenship.

[नागरिकता देने एवं समाप्त करने से सम्बन्धित कानून बना सकती है]

↓

गृह मंत्रालय / Home Ministry

महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019

नोट :– 1. नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है।

1. The Citizenship Amendment Act 1955 has been amended 6 times so far.

2. सितम्बर 2000 में एल.एम सिंघवी की सिफारिश पर – 9 जनवरी 2003 से प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है।

2. On the recommendation of LM Singhvi in September 2000 - Pravasi Bharatiya Divas is being celebrated every year on 9th January 2003.

3. 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष के अन्तराल पर प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है।

3. Since 2015, Pravasi Diwas is being celebrated at an interval of every 2 years.

विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है।

People of Indian origin settled abroad are divided into three categories.

- अनिवासी भारतीय
  Non-Resident Indians
- भारतीय मूल के व्यक्ति
  Person of Indian Origin Overseas
- भारत के सीमापारीय नागरिक
  Citizen of India

नागरिकता संशोधन अधिनियम –2019
Citizenship Amendment Act-2019

- कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बाग्लादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिक्ख, जैन, बौध, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से सम्बन्ध रखता है। तथा 21 दिसम्बर 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रवेश किया है। उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जायेगा।

Any person who belongs to Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Parsi or Christian community of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. and has entered India on or before 21st December, 2014. He will not be considered as an illegal migrant.

- इस अधिनियम में भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है।

  In this act, the mandatory period of residence in India has been reduced from 11 years to 5 years.

- नोटः– इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल के पूर्वी सीमान्त में आने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे।

  Note:- The provisions of this Act will not be applicable to illegal migrants coming to the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura and Eastern Frontier of Bengal.

Polity → मूल अधिकार / Fundamental Right

- भाग / Part - III (3) → मैग्नाकार्टा / Megnacarta
- Art → 12-35
- प्रेरित / Inspired → USA से।

⇒ विश्व में मूल अधिकारों का विकास [Development of Fundamental Rights in the world]

1215 → ब्रिटेन के राजा - सर जॉन द्वारा → लिखित दस्तावेज / written document पेश किया
 - मूल अधिकारों से सम्बन्धित था

IInd लिखित दस्तावेज / written document → 1689 में
 - नाम / Name → [Bill of Rights] → "मूल अधिकारों" का मैग्नाकार्टा कहा [Megnacarta of Fundamental Rights]

फ्रांस / France → King – लुईस XVI
फांसी
1789 में – मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा / The declaration of Rights of men and of the citizens.

अमेरिका :– संविधान / Constitution बना – 1787
– लागू → 1789 में
original constitution में मूल अधिकार / Fundamental Rights नहीं थे
मूल अधिकार / F.R → 1791 में जोड़े / Add on

भारत :- संविधान / Constitution → 26 Nov. 1949 बना

L लागू → 26 Jan. 1950

L मूल अधिकार / Fundamental Rights → भाग / Part - 3
Art. 12-35

L मूल संविधान / original constitution में → Total F.R / कुल मूल अधिकार → 7

वर्तमान / Present → 6 मूल अधिकार

Note :- ⇒ 44 वाँ संविधान संविधान अधिनियम - 1978 - [44th CA - 1978] के द्वारा
Art 19 (1) F, Art 31 → सम्पत्ति का अधिकार / Right to property को भाग / Part-3 से निकाल कर भाग XII में अनु / Art 300 क / 300 A में वैधानिक / Legal Right बना दिया।

21. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? Who can give orders and directions to the government for the enforcement of Fundamental Rights?

DP Const. 20 Nov. 2023

(a) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
Supreme Court and High Courts

(b) भारत के राष्ट्रपति President of India

(c) भारत के प्रधानमंत्री Prime Minister of India

(d) राज्यपाल Governor

22. निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः कार्यालयी कर्त्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्न में से कौन-सी रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? Which of the following writs is issued by a High Court to compel a lower court or a government official to properly perform his essential or purely official duties?

DP Const. 20 Nov. 2023

(a) बन्दी प्रत्यक्षीकरण Habeas Corpus
(b) परमादेश Mandamus
(c) उत्प्रेषण- लेख Letter of Intent
(d) अधिकार पृच्छा quo warranto